Machine Translated by Google

संदर्भ: आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/एमआईएससी/092/04/2021

मैसर्स बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में आदेश।

पर आधारित

(i) बीमा के नियम 4 के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी (एओ) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस (एससीएन) संदर्भ संख्या आईआरडीएआई/एडीजे/बीएजीआईसीएल/02/2019-20 दिनांक 1 नवंबर, 2019 (निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने की प्रक्रिया) नियम, 2016।

(ii) उक्त एससीएन को मैसर्स बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (बीएजीआईसीएल या बीमाकर्ता) दिनांक 7 जुलाई, 2020 की प्रतिक्रिया। (iii) वर्चुअल व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान BAGICL द्वारा AO के समक्ष प्रस्तुतियाँ

22 जुलाई, 2020 को आयोजित किया गया ।

(iv) एओ द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट दिनांक 31 अगस्त, 2020।

(वी) प्राधिकरण का पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 को BAGICL को AO की जांच रिपोर्ट पर अपना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। (vi) प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा दी गई 21 जनवरी, 2021 को 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान BAGICL द्वारा किए गए सबमिशन ।

1। पृष्ठभूमि:

1.1. मोटर बीमा सेवा प्रदाता दिशानिर्देश (एमआईएसपी दिशानिर्देश) के कार्यान्वयन पर विशेष जोर देने के साथ 12 से 14 फरवरी, 2018 तक प्राधिकरण द्वारा मैसर्स बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एक केंद्रित निरीक्षण किया गया था । निरीक्षण में, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बीमाकर्ता मोटर बीमा पॉलिसियों के वितरण और/या सेवा देने के लिए मोटर बीमा सेवा प्रदाता (MISP) के रूप में नियुक्त किए बिना कुछ ऑटोमोबाइल डीलरों के माध्यम से मोटर बीमा व्यवसाय कर रहा था। निरीक्षण के दौरान बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत 1 नवंबर, 2017 से 31 जनवरी, 2018 की अवधि के लिए मोटर बीमा प्रीमियम रजिस्टर के आधार पर , यह देखा गया कि बीमाकर्ता ने ऑटोमोबाइल डीलरों के माध्यम से बीमा व्यवसाय का लेन-देन किया था जिन्हें एमआईएसपी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था।

1.2. जैसा कि बीमाकर्ता की उपरोक्त कार्रवाई बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी (8) के उल्लंघन में प्रतीत होती है, मामला धारा के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी को भेजा गया था।
29 जनवरी, 2019 को बीमा अधिनियम, 1938 की 105सी । निरीक्षण रिपोर्ट के अन्य निष्कर्षों का निष्कर्ष दिनांक 13 सितंबर, 2019 के आदेश में दिया गया था।

Machine Translated by Google

1.3. निर्णायक अधिकारी ने बीमाकर्ता को 1 नवंबर, 2019 को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया । बीमाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 7 जुलाई, 2020 के द्वारा एससीएन को प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। बीमाकर्ता के अनुरोध के अनुसार, एओ ने उन्हें 22 जुलाई, 2020 को व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी।

1.4. न्यायनिर्णायक अधिकारी ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 105सी के तहत 10,00,000/- रुपये (केवल दस लाख रुपये) के जुर्माने की सिफारिश करते हुए, 31 अगस्त, 2020 को प्राधिकरण को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

1.5. निर्णायक अधिकारी की जांच रिपोर्ट बीमाकर्ता को पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से भेजी गई थी। बीमाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 6 नवंबर, 2020 के माध्यम से उत्तर दिया और व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की, जिसे 21 जनवरी, 2021 को प्रदान किया गया।

1.6. बीमाकर्ता की ओर से श्री तपन सिंघेल, एमडी और सीईओ, श्री रमनदीप साहनी, सीएफओ, श्री आदित्य शर्मा, प्रमुख-मोटर व्यवसाय, श्री गुरनीश खुराना, मोटर एलओबी के प्रमुख और श्री ओंकार कोठारी, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी उपस्थित थे। सुनवाई। आईआरडीएआई की ओर से, श्री रणदीप सिंह जगपाल, मुख्य महाप्रबंधक (मध्यस्थ), श्रीमती। यज्ञप्रिय भरत, मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन), श्री के. महिपाल रेड्डी, महाप्रबंधक (एनएल) और श्री ए. रामा सुधीर, प्रबंधक (एनएल) ने सुनवाई में भाग लिया।

1.7. एससीएन दिनांक 1 नवंबर, 2019 में उल्लिखित उल्लंघन, एससीएन के जवाब में बीमाकर्ता की प्रस्तुतियाँ, एओ का विश्लेषण और सिफारिश, बीमाकर्ता की लिखित प्रस्तुतियाँ और 21 तारीख को आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुतियाँ

नीचे दिए गए निर्णय पर पहुंचने के लिए जनवरी, 2021 की सावधानीपूर्वक जांच की गई है।

2. चार्ज:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी (8) का उल्लंघन:

2.1. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी की उप-धारा (8) के अनुसार: `कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के तहत पंजीकृत होने के बिना एक मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, वह दंड के लिए उत्तरदायी होगा जो विस्तारित हो सकता है दस लाख रुपये तक और कोई भी व्यक्ति जो एक मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करता है या कोई व्यक्ति जो इस तरह से कार्य करने के लिए पंजीकृत नहीं है या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से भारत में किसी भी बीमा व्यवसाय का लेन-देन करता है, वह दंड के लिए उत्तरदायी होगा जो एक करोड़ रुपये तक हो सकता है। `.

सर्वे नं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, भारत | Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, India
: +91-40-2020 4000 वेबसाइट : www.irdai.gov.in | : +91-40-2020 4000 Website : www.irdai.gov.in

Machine Translated by Google

2.2. BAGICL बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42D (8) के उल्लंघन में इसके माध्यम से बेचे जाने वाले ऑटोमोटिव वाहनों की मोटर बीमा पॉलिसियों को वितरित और / या सेवा देने के लिए मोटर बीमा सेवा प्रदाता (MISP) के रूप में नियुक्त किए बिना ऑटोमोबाइल डीलरों के माध्यम से मोटर बीमा व्यवसाय कर रहा था। 1 नवंबर, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक मोटर बीमा प्रीमियम रजिस्टर से पता चला कि बीमाकर्ता ने इस तरह के बीमा व्यवसाय का लेन-देन किया है।

3. एससीएन को बीमाकर्ता की प्रस्तुतियों का सारांश:

3.1. बीमाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि एससीएन दिनांक 1 नवंबर, 2019 की विषय वस्तु की पहले ही जांच की जा चुकी है और प्राधिकरण द्वारा निष्कर्ष निकाला जा चुका है। कंपनी को दोहरे खतरे के अधीन नहीं होना चाहिए।

3.2. बीमाकर्ता ने धारा 42डी (8) और (9) और 2 (10) (ए) के प्रावधानों का हवाला दिया - [जिसका बीमा अधिनियम, 1938 के 2 (10 बी) के बजाय गलत तरीके से उल्लेख किया गया है], धारा 2 (1) (एफ) IRDA अधिनियम, 1999, MISP दिशानिर्देश 4(a) और IRDAI (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यस्थों को कमीशन या पारिश्रमिक या पुरस्कार का भुगतान)

विनियम, 2016 और प्रस्तुत किया कि उनका मानना है कि एमआईएसपी बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी (8) और (9) के दायरे में नहीं आते हैं और एमआईएसपी दिशानिर्देशों के संबंध में उल्लंघन, यदि कोई हो, धारा 105सी के दायरे में नहीं आते हैं। बीमा अधिनियम, 1938 के न्यायनिर्णयन प्रक्रिया की आवश्यकता है।

3.3. कंपनी के पास कई मोटर डीलरों के साथ बुनियादी सुविधाओं को साझा करने की व्यवस्था थी। MISP दिशानिर्देशों के प्रारंभ में, MISP दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए ऐसी व्यवस्थाओं को समाप्त करना पड़ा। हालांकि, ग्राहकों के लिए सेवाएं प्रभावित नहीं हो सकीं। मोटर डीलरों से व्यवसाय की सोर्सिंग को तब तक रोकना जब तक कि वे MISP दिशानिर्देशों के तहत सभी अनुपालनों को पूरा नहीं कर लेते, यह ग्राहकों के लिए एक अहितकारी और पॉलिसीधारकों के हित के प्रतिकूल होता। बीमाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि एससीएन के अनुबंधों में संदर्भित डीलरों को केवल नामांकित किया गया था और एमआईएसपी दिशानिर्देशों की अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए एमआईएसपी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन उनके माध्यम से मोटर बीमा कारोबार किया था। इसके अलावा, बीमाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि नामांकन के बाद, कुछ ऑटोमोटिव डीलरों की नियुक्ति एमआईएसपी के रूप में उनकी नियुक्ति को आगे बढ़ाने की उनकी अनिच्छा के कारण समाप्त कर दी गई थी।

4. जांच रिपोर्ट का विश्लेषण और सिफारिश:

Machine Translated by Google

4.1. जांच रिपोर्ट में एओ ने स्पष्ट किया है कि बीमाकर्ता का तर्क है कि वर्तमान मामले की जांच प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 13 के द्वारा की जा चुकी है।
सितंबर 2019 गलत है। जबकि निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 12 अप्रैल, 2018 से निकलने वाले अन्य मुद्दों को उक्त आदेश में निपटाया गया था, अवलोकन संख्या। निरीक्षण रिपोर्ट के 9 जो कि निर्णायक कार्यवाही का आधार है, उसमें निष्कर्ष नहीं निकाला गया था।

4.2. एओ की जांच रिपोर्ट के अनुसार, एमआईएसपी के रूप में लाइसेंस प्राप्त नहीं होने वाले ऑटोमोबाइल डीलरों को बीएजीआईसीएल द्वारा बीमा व्यवसाय के मध्यस्थता के लिए नियुक्त किया गया था। बीमाकर्ता का यह तर्क कि 31 अगस्त, 2017 से 31 अक्टूबर, 2017 तक की अवधि नए वितरण ढांचे में निर्बाध प्रवास के लिए पर्याप्त नहीं थी, मान्य नहीं है। एमआईएसपी दिशानिर्देश 1 नवंबर, 2017 को लागू होंगे, यह सभी सामान्य बीमाकर्ताओं को पहले से पता था। बीमाकर्ता द्वारा 'नामांकन' और 'नियुक्ति' के बीच अंतर करने का प्रयास केवल इस मामले को उलझाता है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि व्यवसाय इन संस्थाओं के माध्यम से उन्हें एमआईएसपी के रूप में नियुक्त किए बिना प्राप्त किया गया था।

4.3. एओ ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद और बीमाकर्ता द्वारा गैर-अनुपालन, पॉलिसीधारकों को नुकसान और गैर-अनुपालन की दोहराव की प्रकृति के माध्यम से अनुपातहीन लाभ या अनुचित लाभ के कारकों का विश्लेषण करने के बाद, रुपये के जुर्माना की सिफारिश की है। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42D (8) के उल्लंघन के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 105C के तहत 10,00,000 / - (केवल दस लाख रुपये)।

5. एओ की जांच रिपोर्ट पर और उसके दौरान बीमाकर्ता के सबमिशन का सारांश व्यक्तिगत सुनवाई:

5.1. बीमाकर्ता ने दोहराया कि ऑटोमोटिव डीलरों को MISP दिशानिर्देशों के अनुरूप लाने के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं को ओवरहाल करने के लिए उद्योग को दो महीने का बेहद कम समय दिया गया था। BAGICL और डीलरों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, अभी भी कुछ ऑटोमोटिव डीलर थे जिन्होंने BAGICL के साथ नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन BAGICL द्वारा MISP के रूप में 1 नवंबर, 2017 की देय तिथि तक लंबित आवश्यकताओं के कारण नियुक्त नहीं किया गया था। इस अवधि के दौरान डीलर MISP की कोई भी पूरी जिम्मेदारी या दायित्व नहीं लेंगे, लेकिन ग्राहकों को BAGICL से परिचित कराना जारी रखेंगे। हालांकि, BAGICL ने सुनिश्चित किया कि इन प्रस्तावित MISP को कोई भुगतान/प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। व्यवस्था का उद्देश्य बहुत ही कम समय की संक्रमणकालीन अवधि के लिए होना था। प्रस्तावित एमआईएसपी में से कोई भी पॉलिसीधारकों या बीमाकर्ता के लिए सुविधा सेवाओं की नीतियों की सर्विसिंग में संलग्न नहीं है।

वे केवल मोटर बीमा प्राप्त करने के लिए BAGICL को संभावनाओं को निर्देशित करने में शामिल थे।

5.2. बीमाकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि एक ऑटो डीलर जिसे MISP दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के आसपास के संक्रमणकालीन चरण के दौरान BAGICL से कोई भुगतान प्राप्त किए बिना केवल BAGICL में एक ग्राहक का परिचय देना है

Machine Translated by Google

BAGICL द्वारा MISP के रूप में प्रायोजित होने की प्रत्याशा को अधिनियम की धारा 42D (8) के अर्थ में बीमा व्यवसाय में मध्यस्थता या लेनदेन नहीं माना जा सकता है। अधिक से अधिक ऐसे डीलर को परिचयकर्ता के रूप में माना जा सकता है जो बीमाकर्ता के लिए एमआईएसपी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया में बीमाकर्ता से बिना किसी प्रोत्साहन के इस गतिविधि का संचालन कर रहा है।

5.3. बीमाकर्ता ने कहा है कि केवल तथ्य यह है कि BAGICL ने संबंधित डीलरों के लिए डीलरों द्वारा किए गए परिचय की निगरानी के लिए कुछ आंतरिक 'IMD' कोड निर्दिष्ट किए थे, यह नहीं माना जा सकता है कि BAGICL ने डीलर को मध्यस्थ या MISP के रूप में नियुक्त किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसे कोड डीलरों को नहीं बताए गए थे और केवल BAGICL के आंतरिक उपयोग के लिए थे।

5.4. बीमाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि जबकि प्रस्तावित MISP की संभावनाओं को पेश करने की प्रथा को एक अनियमित उपाय के रूप में देखा जा सकता है, यह केवल तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए बहुत ही कम समय तक चला जब डीलर MISP के तहत निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने की प्रक्रिया में थे। दिशानिर्देश।

5.5. बीमाकर्ता ने कहा कि ग्राहकों को पेश करने वाले प्रस्तावित एमआईएसपी की प्रथा स्पष्ट रूप से उनकी नियुक्ति की प्रत्याशा में थी और बीएजीआईसीएल के साथ एमआईएसपी के रूप में दीर्घकालिक संबंध जारी रखा। BAGICL को यह स्पष्ट हो जाने के बाद कि डीलर MISP के रूप में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, इस प्रथा को विधिवत बंद कर दिया गया था और फरवरी, 2018 में हुए निरीक्षण से पहले ही इन परिचयों को रोक दिया गया था। बीमाकर्ता ने आगे कहा कि BAGICL ने आय से अधिक लाभ प्राप्त नहीं किया है या अनुचित लाभ जो प्रस्तावित एमआईएसपी की शुरूआत के परिणामस्वरूप बीएजीआईसीएल द्वारा प्राप्त व्यवसाय से संबंधित कमीशन/शुल्क की राशि से मात्रात्मक है।

5.6. व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान, बीमाकर्ता ने एओ की जांच रिपोर्ट के जवाब में लिखित निवेदन को दोहराया। इसके अलावा, बीमाकर्ता ने पुष्टि की कि इन संस्थाओं के माध्यम से खरीदे गए व्यवसाय को 31 मार्च, 2018 तक रोक दिया गया था और प्रस्तुत किया कि वितरण शुल्क को रोक कर रखा गया था। इसके अलावा, बीमाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी (8) एक अन्य बीमाकर्ता को जारी प्राधिकरण के आदेश और बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 में मध्यस्थों की परिभाषा के साथ पढ़ने के मद्देनजर एमआईएसपी पर लागू नहीं होती है।

6. निर्णय:

Machine Translated by Google

6.1. व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान, बीमाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त शुल्क पहले से ही प्राधिकरण के आदेश दिनांक 13 सितंबर, 2019 में शामिल था और वर्तमान व्यक्तिगत सुनवाई इसी विषय पर क्रम में तीसरी है। यह दिखाने के लिए कहा गया कि 13 सितंबर, 2019 के आदेश में 13 में से किस आरोप के तहत उपरोक्त उल्लंघन को कवर किया गया था, बीमाकर्ता कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

बीमाकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 15 जनवरी, 2020 में यह चिंता व्यक्त की गई है कि कंपनी को दोहरे जोखिम के अधीन नहीं किया जाना चाहिए, एओ की जांच रिपोर्ट में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है और इस आदेश के पैरा 4.1 में बिंदु को भी संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

6.2. इस प्रकार, बीमाकर्ता का यह तर्क कि प्रभार की पहले ही जांच की जा चुकी है और प्राधिकरण द्वारा निष्कर्ष निकाला जा चुका है, मान्य नहीं है। एमआईएसपी के रूप में नियुक्त किए बिना बीमाकर्ता के साथ मोटर बीमा व्यवसाय रखने वाली संस्थाओं से संबंधित निरीक्षण निष्कर्ष बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी (8) का उल्लंघन है जिसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 105सी के तहत न्यायनिर्णयन प्रक्रिया अनिवार्य है। तदनुसार, बीमा (निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने की प्रक्रिया) नियम, 2016 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

6.3. बीमाकर्ता ने यह भी बताया है कि एमआईएसपी बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी (8) और (9) के दायरे में नहीं आते हैं और एमआईएसपी दिशानिर्देशों का उल्लंघन यदि कोई हो, धारा 105सी के दायरे में नहीं आता है। बीमा अधिनियम, 1938 न्यायनिर्णयन प्रक्रिया की अपेक्षा करता है।

6.4. निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, BAGICL कुछ ऑटोमोबाइल डीलरों के माध्यम से उन्हें मोटर बीमा सेवा प्रदाता (MISP) के रूप में नियुक्त किए बिना मोटर बीमा व्यवसाय का लेन-देन कर रहा था। एमआईएसपी दिशानिर्देशों के दिशानिर्देश 3 (एफ) एमआईएसपी को बीमाकर्ता या बीमा मध्यस्थ द्वारा इसके माध्यम से बेचे जाने वाले ऑटोमोटिव वाहनों की मोटर बीमा पॉलिसियों को वितरित और/या सेवा देने के लिए नियुक्त एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में परिभाषित करता है। 2017 में MISP पर दिशानिर्देशों की शुरूआत के माध्यम से, ऑटोमोबाइल डीलरों को बीमाकर्ता / मध्यस्थ और MISP के बीच किए गए एक समझौते के आधार पर मोटर बीमा पॉलिसियों को वितरित और सेवा करने की अनुमति दी गई थी।

6.5. BAGICL ने मोटर बीमा व्यवसाय के लेन-देन के लिए कुछ ऑटोमोबाइल डीलरों को नियुक्त किया है। यह स्पष्ट है कि यहां ये संस्थाएं एमआईएसपी के रूप में नहीं लगी हैं क्योंकि एमआईएसपी दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक इस आशय का कोई समझौता नहीं था।
इसलिए, इस उदाहरण में BAGICL द्वारा लगाए गए ऑटोमोबाइल डीलरों को बीमा व्यवसाय मांगने और रखने के लिए अनधिकृत हैं। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42डी (8) को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि बीमाकर्ता की कार्रवाई धारा 42डी (8) के प्रावधानों को आकर्षित करती है जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ या किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है। ऐसे किसी व्यक्ति के माध्यम से भारत में इस तरह से कार्य करने के लिए पंजीकृत नहीं है या किसी बीमा व्यवसाय का लेन-देन नहीं करता है, तो वह एक करोड़ रुपये तक के दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

6.6. एमआईएसपी दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी ऑटोमोबाइल डीलर जैसा कि दिशानिर्देश 3(सी) में परिभाषित है और जो धारा 42 में निर्धारित किसी भी अयोग्यता को आकर्षित नहीं करता है।

Machine Translated by Google

बीमा अधिनियम, 1938 MISP बनने के लिए पात्र होगा। यह ध्यान में रखते हुए कि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42 उनकी पात्रता के लिए MISP पर लागू होती है, धारा 42D (8) के प्रावधानों को अप्रवर्तनीय नहीं माना जा सकता है यदि ऑटोमोबाइल डीलरों को MISP के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है और अनधिकृत व्यक्तियों की क्षमता में बीमा व्यवसाय का संचालन करते हैं। . वास्तव में, MISP दिशानिर्देशों के लिए आवश्यक है कि MISP बीमा अधिनियम, 1938, IRDA अधिनियम, 1999, उसके तहत बनाए गए विनियमों, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों और परिपत्रों के प्रावधानों का भी पालन करेगा।

6.7. बीमा अधिनियम की धारा 42डी (8) अनधिकृत संस्थाओं या बीमा कारोबार में लगे व्यक्तियों से निपटने के लिए है। उस अनुभाग का फोकस जिसे कोई भी व्यक्ति भारत में किसी बीमा व्यवसाय के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकृत नहीं है या लेनदेन करता है

तत्काल मामले में इसे लागू करते समय अनदेखी नहीं की जाएगी। उक्त धारा में न केवल ऐसे किसी व्यक्ति को शामिल किया गया है जो इस तरह कार्य करने के लिए पंजीकृत नहीं है या भारत में किसी बीमा व्यवसाय का लेन-देन नहीं करता है, बल्कि उन्हें शामिल करने के लिए कड़े दंड का प्रावधान करता है।

6.8. यदि BAGICL की उपरोक्त व्याख्या (पैरा 6.3) को स्वीकार कर लिया जाता है, तो कोई भी बीमा कंपनी, अपंजीकृत संस्थाओं या व्यक्तियों को बीमा व्यवसाय करने के लिए संलग्न कर सकती है और बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42D (8) के तहत पूछताछ नहीं की जाएगी। इस तरह की व्याख्या अपंजीकृत व्यक्तियों के माध्यम से बीमा कारोबार का दुरुपयोग करने के लिए बीमाकर्ता को बेलगाम लाइसेंस देगा। इसलिए, 'BAGICL' द्वारा दी गई व्याख्या कि धारा 42D (8) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 105C के साथ पढ़ी जाती है, इस मामले में न्यायनिर्णयन प्रक्रिया की आवश्यकता लागू नहीं है, गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

6.9. बीमाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि मोटर डीलरों से व्यवसाय की सोर्सिंग को तब तक रोकना जब तक कि वे MISP दिशानिर्देशों के तहत सभी अनुपालन पूरा नहीं कर लेते, ग्राहकों के लिए अहित और पॉलिसीधारकों के हितों के प्रतिकूल होता। यह अपंजीकृत संस्थाओं के साथ बीमा कारोबार के लेन-देन का वैध औचित्य नहीं हो सकता। यह ध्यान दिया जाता है कि बीमाकर्ता ने एमआईएसपी दिशानिर्देशों के शुरू होने से पहले 56 ऑटोमोटिव डीलरों के साथ कथित तौर पर बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने के लिए समझौते किए थे और इन समझौतों को 31 अक्टूबर, 2017 तक समाप्त कर दिया गया था।

6.10. इसके अलावा, पैरा 6.9 में बीमाकर्ता द्वारा दिया गया तर्क एससीएन में सूचीबद्ध 34 ऑटोमोटिव डीलरों के लिए मान्य नहीं है क्योंकि यह पाया गया है कि इन डीलरों के पास 1 नवंबर, 2017 से पहले भी कोई समझौता नहीं था , लेकिन वे नियुक्त किए बिना मोटर बीमा व्यवसाय कर रहे थे। एमआईएसपी के रूप में। ये सभी 90 ऑटोमोटिव डीलर बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42D (8) के संदर्भ में अपंजीकृत संस्थाओं या व्यक्तियों के समान स्तर पर खड़े थे।

Machine Translated by Google

6.11. बीमाकर्ता का यह निवेदन कि इन ऑटोमोटिव डीलरों के साथ यह व्यवस्था एक छोटी संक्रमणकालीन अवधि के लिए थी, को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी कोई संक्रमणकालीन अवधि की परिकल्पना नहीं की गई थी।

6.12. इसके अलावा, बीमाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वितरण शुल्क वापस ले लिया गया था। हालांकि, भुगतान न करना या वितरण शुल्क रोकना बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी (8) के प्रावधानों के उल्लंघन का औचित्य नहीं हो सकता क्योंकि ये मोटर बीमा व्यवसाय अपंजीकृत संस्थाओं / व्यक्तियों के माध्यम से किए गए थे।

6.13. बीमाकर्ता ने व्यक्त किया कि उनकी कंपनी का सबसे पहले निरीक्षण किया गया था और उनके पास MISP मामलों को निश्चित क्रम में रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इस संबंध में, यह सराहना की जा सकती है कि 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी एमआईएसपी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए सभी सामान्य बीमाकर्ता एक ही विमान पर थे और सभी बीमाकर्ताओं द्वारा कार्यान्वयन के लिए दो महीने का समय भी उपलब्ध था। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि निरीक्षण के निष्कर्ष अलग होते, चाहे वह एमआईएसपी दिशानिर्देशों के शुरू होने के तीन महीने बाद या बाद की तारीख में आयोजित किया गया हो, क्योंकि निरीक्षण के समय के बावजूद भौतिक तथ्य समान रहे होंगे।

6.14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, बीमाकर्ता ने नवंबर, 2017 से जनवरी, 2018 तक बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी (8) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 2,214 मोटर की याचना की। 90 अपंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से 1,44,61,677 रुपये के प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी।

6.15. बीमाकर्ता ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान स्वीकार किया कि उपरोक्त अपंजीकृत व्यक्तियों के माध्यम से बीमा व्यवसाय का लेन-देन 31 मार्च, 2018 तक जारी रहा, जिससे बीमा पॉलिसियों की संख्या और प्रीमियम की राशि में और वृद्धि होगी।

6.16. न्यायनिर्णयन अधिकारी ने रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। 10,00,000 के तहत बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 105सी।

6.17. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी (8) के उल्लंघन की प्रकृति और मात्रा को ध्यान में रखते हुए। मैं न्यायनिर्णयन अधिकारी की सिफारिश से सहमत हूं।

6.18. तदनुसार, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 105सी के तहत प्राधिकरण पर निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रु. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी (8) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए बीमाकर्ता पर एतद्द्वारा 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) लगाया जाता है।

Machine Translated by Google

7. रुपये का जुर्माना। एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर शेयरधारकों के खाते को नामे करके बीमाकर्ता द्वारा 10,00,000/- (केवल दस लाख रुपए) प्रेषित किए जाएंगे (जिसके लिए विवरण सूचित किया जाएगा) अलग से)। दंड के प्रेषण की सूचना श्रीमती को भेजी जाएगी। यज्ञप्रिय भारत, मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन), आईआरडीएआई, पद सं. 115/1, वित्तीय जिला, नानकरंगुडा, हैदराबाद-500032।

8. आगामी बोर्ड बैठक में आदेश बीमाकर्ता के बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा और बीमाकर्ता प्राधिकरण को बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति प्रदान करेगा।

9. यदि बीमाकर्ता इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की जा सकती है।

एसडी/-

(डॉ. सुभाष सी. खुंटिया)
अध्यक्ष

जगह: हैदराबाद
दिनांक: 15 अप्रैल, 2021